रही है, वे हैं:- अपनी-अपनी ऋण मूल्यांकन मशीनरी को सुदृढ़ बनाने की आवश्यकता और अग्रिमों पर गहन निगरानी तथा उन पर नियंत्रण बनाए रखना, अनुपयोज्य आस्तियों की वसूली में सुधार और अपने ऊपरी खर्चों में कमी लाना, कमजोर वित्तीय स्थिति वाले बैंकों द्वारा आर बी आई की स्वीकृति के बिना पूंजीगत व्यय/शाखा विस्तार करने में अंकुश लगाना। जब कभी स्टाफ का उत्तरदायित्व सुनिश्चित हो जाता है तो बैंक उन पर लागू आचरण नियमावली के अनुसार, उपयुक्त कार्रवाई करते हैं।

राज्य सरकारों की शोचनीय वित्तीय स्थिति

87. **श्री बरजिन्दर सिंह:**
श्री राज मोहिन्दर सिंह:

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि चालू वर्ष में औद्योगिक मंदी के कारण पंजाब सहित अनेक राज्य सरकारों की आर्थिक स्थिति शोचनीय हो गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या यह भी सच है कि इन सरकारों ने इस आर्थिक संकट पर नियंत्रण पाने के लिए केन्द्र सरकार से सहायता मांगी है;

(ग) यदि हां, तो क्या चालू वर्ष में सरकार द्वारा कितनी वित्तीय सहायता प्रदान की गई है, विशेष रूप से पंजाब को; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

वित्त मंत्री (श्री यशवंत सिन्हा): (क) से (घ) विविध कारणों से अपनी अस्थायी वित्तीय कठिनाइयों से जूझने के लिए पंजाब सहित विभिन्न राज्य सरकारों ने वित्तीय सहायता मांगी है।

पंजाब के मामले में, राज्य सरकार की हकदारी के अनुसार जारी अग्रिम के अलावा, जब भी आवश्यक हुआ है, राज्य की प्राप्तियों और व्यय के बीच के अस्थायी विसंगति से निपटने के लिए राज्य को अधौषाय अग्रिम भी जारी किए थे। वर्ष 1998-99 के दौरान पंजाब को अब तक दी गई और जारी की गई केन्द्रीय सहायता आबंटन को दर्शाने वाला एक विवरण संलग्न है।

विवरण

वर्ष 1998-99 के दौरान पंजाब को अब तक दी गई और जारी की गई केन्द्रीय सहायता का आबंटन

(करोड़ रुपए में)

	मदें	1998-99 (अब तक)	
		आबंटन	जारी की गई
1.	सामान्य केन्द्रीय सहायता	207.88	191.39
2.	न्यूनतम मूलभूत सेवाएं	38.94	31.28
3.	स्लम विकास स्कीम	9.04	8.25
4.	सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम	8.82	---@
5.	त्वरित सिचाई लाभ कार्यक्रम	150.00	---@
6.	बाह्य सहायता प्राप्त परियोजनाओं के लिए अतिरिक्त केन्द्रीय सहायता	281.20	141.33
7.	दशमेश अकादमी ऑफ मार्शल स्पोर्टस, आनन्द पुर साहिब के लिए अतिक्ति केन्द्रीय सहायता	7.50	7.50
8.	सीमा क्षेत्र में किसानों की मुसीबतों को कम करना	8.00	---@
9.	यूनीवर्सटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, फरीदकोट-लाइब्रेरी साईंसेज	1.00	---@

@ अभी तक जारी नहीं की गई।

Mobilisation of Resources

88. DR. B.B. DUTTA: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the target set for the mobilisation of resources through Taxation (both direct and indirect taxes) and disinvestment in Public Sector Enterprises during 1998-99;

(b) how far these targets have been achieved;

(c) what are the reasons for shortfalls on both fronts; and

(d) in what manner Government propose to meet the shortages experienced in mobilisation of resources through taxation and disinvestment in PSEs?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING REVENUE AND INSURANCE): (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) and (b) Sir, Targets and the amounts collected so far, are given below:

(Rs. in crores)

	Targets	Amount Collected (upto Jan. 1992)
1. Direct Taxes	48400	31639.60
2. Indirect Taxes	107440	74124.19
3. Disinvestment	5000	1188.00

(c) and (d) Whether there is a shortfall in overall revenue collection or not, will be known only at the end of the current financial year.

Impact of Lowering of Interest Rates on Small Saving Schemes On the Resources of States

89. SHRI NILOTPAL BASU:
SHRI DIPANKAR MUKHERJEE:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether there is any proposal by the Government to make good the disadvantage to the State Governments whose resources for investment will be severely impaired due to lowering of interest rates for small saving schemes as announced by Government, recently;

(b) if so, the details thereof; and

(c) if not, the reasosn therefor?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) No, Sir. The revision of the interest rates on small savings schemes is not likely to result in a fall in collections under small savings. Consequently, there is no reason to expect that the resources of State Governments from small savings will be impaired.

(b) Does not arise.

(c) Not applicable.

Financial Crisis Being faced by Orissa Government

90. SHRI SANATAN BISI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether it is a fact that Government of Orissa is facing financial crisis as reported in Oriya "Samaj" dated 1st February 1999; and

(b) if so, what are the details in this regard?

THE MINISTER OF FINANCE (SHRI YASHWANT SINHA): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

Sicks Units of Gujarat Pending with BIFR

91. SHRI BANGARU LAXMAN: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the details of sick units of Gujarat pending with BIFR;

(b) whether Government propose to sell these sick units; and

(c) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (BANKING, REVENUE AND INSURANCE (SHRI KADAMBUR M.R. JANARTHANAN): (a) The Board for Industrial and Financial Reconstruction (BIFR) has reported that as on 31st January, 1999 cases of 69 companies from Gujarat are pending with BIFR at various stages (status is given in the statement) (*See* below)

(b) and (c) The action regarding sale, restructuring, winding up etc. of the companies registered with BIFR is taken as per the provisions of Sick Industrial Companies (Special provisions) Act, 1985 (SICA).